आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 23.07.2024
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया।
- बजट में पांच वर्ष की अवधि में चार करोड से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढाने की पांच योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नीट–यूजी 2024 परीक्षा दोबारा कराने से इनकार किया।
- मुख्य सचिव ने प्रदेश के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।

बजट–1

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024–25 का आम बजट पेश किया। यह नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमति सीतारामण ने सातवीं बार बजट पेश किया है। वित्तमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कीं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। तीन से सात लाख रुपए तक की आय पर पांच प्रतिशत, सात सात से दस लाख रुपए तक दस प्रतिशत, दस से बारह लाख रुपए तक पंद्रह प्रतिशत, बारह से पंद्रह लाख रुपए तक बीस प्रतिशत और पंद्रह लाख रुपए से अधिक आय पर तीस प्रतिशत तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17 हजार पांच सौ रुपए तक की बचत हो सकेगी।

बजट–2

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। इसमें पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारम्भ करना शामिल है। वित्तवर्ष 2022–23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ।
बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एम एस एम ई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है।
प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सीडी के रूप में एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केन्द्रित होगी। वित्तमंत्री ने बताया कि कृषि और सबंधित क्षेत्रों के लिए एक लाख 52 हजार करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट–3

वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। अगले दो वर्ष में पूरे देश में एक करोड किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण–पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। दस हजार आवश्यकता आधारित संसाधन केन्द्र स्थापित किये जाएंगे।

वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड रुपये का निवेश करेगी।

बजट पेश किये जाने के बाद, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने दिनभर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

वीडियो संदेश /प्रतिक्रिया

बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि यह बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। ये बजट गांव, ग्रामीण और युवाओं का बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से भारत को वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनाने में मदद मिलेगी। उधर, कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है।

बजट प्रतिक्रया– मुख्यमंत्री

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय बजट में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख रुपए किया जाना ऐतिहासिक निर्णय है। इसके माध्यम से देश के गैर–कॉर्पोरेट, गैर–कृषि लघु, सूक्ष्म उद्यम और अधिक सशक्त होंगे। निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों के मजबूत होने से देश की आर्थिकी सशक्त होगी। केंद्रीय बजट 2024–25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए श्री धामी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट–यूजी 2024 परीक्षा दोबारा करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रणालीगत उल्लंघन या परीक्षा की शुचिता पर किसी भी तरह के प्रभाव का कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाना न्यायोचित नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हई।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक सवाल के दो उत्तर विवाद में आईआईटी दिल्ली के उत्तर को सही माना। एक विकल्प को सही मानने पर अब एनटीए को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। एनटीए ने पूर्व में किसी भी विकल्प को न चुनने वाले छात्रों को अंक दिए थे।

बैठक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज को उत्तराखंड के अंब्रेला ब्रांड के रूप में स्थापित करते हुए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने को कहा। सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हाउस ऑफ हिमालयाज की बोर्ड ऑफ गर्वनेस की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय महिला उद्यमियों को

प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सभी उत्पादों को एक ही नाम व ब्रांड मिलने से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा। श्रीमती रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता लेने के निर्देश दिए।

मौसम

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनज़र आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है।
उधर, पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र मदकोट का दौरा कर देवीबगड़ और भैरोबगड़ गांव में मंदाकिनी नदी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने जिलाधिकारी के सामने आपदा प्रभावितों के विस्थापन का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने समाधान का आश्वासन दिया।

अवकाश

कांवड़ मेले के तहत हरिद्वार जिले में कक्षा पहली से बाहरवीं तक सभी सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्र 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान शहर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने के चलते भीड़ प्रबंधन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वहीं, हरिद्वार बस अड्डा आज से कांवड़ मेला सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए ऋषिकुल मैदान में स्थानांतरित रहेगा। शहर में भीड़ बढ़ने के कारण बसों का संचालन ऋषिकुल बस अड्डे से ही किया जाएगा।

गोल्डन कार्ड

श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर गोल्डन कार्ड की सुविधा मिली। है। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज मंदिर कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड सौंपे। गौरतलब है कि कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के तहत कैशलेश उपचार की सुविधा मिलेगी।